भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 459

दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ

मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना

†459. श्री गणेश सिंहः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), स्वामित्व, ई-पंचायत और जीपीडीपी योजनाओं को मध्य प्रदेश, विशेषकर सतना जिले में अब तक किस स्तर पर क्रियान्वित किया गया है और इन योजनाओं का स्थानीय पंचायतों के शासन, नियोजन और संपत्ति विवाद निपटान दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या वर्ष 2018-24 के दौरान सतना जिले की पंचायतों को किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रोत्साहन योजना (जैसे पंचायतों का प्रोत्साहन) में चिहिनत किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उन पंचायतों के नाम और वे मानदंड क्या हैं जिनके आधार पर उनकी पहचान की गई है; और

(घ) क्या सरकार की ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श जनभागीदारी और स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सतना जिले को और सुदृढ़ बनाने हेतु किसी पायलट क्लस्टर, डिजिटल पंचायत योजना या विशेष परियोजना को क्रियान्वित करने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्य सरकारों के प्रयासों को निरंतर आधार पर पूरक और संपूरित करता है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सुदृढ़ीकरण और कुशल कामकाज की दिशा में योजनाओं के तहत निधि सहायता भी शामिल है।
पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

i. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और उनके पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत करना और ग्राम पंचायत भवन और कम्प्यूटरीकरण जैसे बुनियादी ढांचे को सहायता प्रदान करना है।

ii. पंचायतों को प्रोत्साहन (आईओपी) पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करने के लिए आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक, जिसके तहत सेवा प्रदायगी और लोक कल्याण में सुधार के लिए उनके अच्छे काम को मान्यता देते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं, और

iii. ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ईपंचायत) आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक, जिसके तहत पंचायतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और उनके समग्र परिवर्तन में योगदान देने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है।

ये योजनाएं मध्य प्रदेश के सतना जिले सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कार्यान्वित की जाती हैं।

इसके अलावा, गाँवों में आवास वाले ग्रामीण परिवारों को 'अधिकारों का अभिलेख' प्रदान करने के लिए कई अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश राज्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण (स्वामित्व) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत, ड्रोन सर्वेक्षण के बाद गृह स्वामियों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, संपत्ति विवादों को कम करना है। मध्य प्रदेश में, 43,014 आबादी गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और लगभग 37,000 गाँवों के लिए 43 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। सतना जिले में, 857 आबादी गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और 553 गाँवों के लिए 27,360 संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

ग्राम पंचायतें अपने संसाधनों का उपयोग करके और विभिन्न स्रोतों से संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से पंचायतों के विकास के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करती हैं। इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को आरजीएसए योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 2022-23 से और आज तक 6,15,600 कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों को जीपीडीपी की तैयारी सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है। मध्य प्रदेश में, 23,005 ग्राम पंचायतों (कुल 23,011 में से) ने ई-पंचायत एमएमपी योजना के तहत विकसित ईग्रामस्वराज पोर्टल पर अपनी जीपीडीपी तैयार और अपलोड की। इसके अलावा, मेरी पंचायत, ऑडिटऑनलाइन, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) और जीईएम प्लेटफॉर्म आदि के साथ ईग्रामस्वराज के एकीकरण जैसे अनुप्रयोगों ने जमीनी स्तर पर शासन में पारदर्शिता और दक्षता लाई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2018-24 के दौरान, पंचायतों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सतना जिले की किसी भी पंचायत को पुरस्कृत/प्रोत्साहित नहीं किया गया है।
(घ) जी, नहीं।

***